International Journal of Business Economics and Management Research
Vol. 14, Issue 6, June 2023 Impact Factor: 8.857 ISSN: (2229-4848)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधान

डॉ0 मधुप्रभा तिवारी

एसो. प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग

कालपी कॉलेज, कालपी

शोध सारांश

भारत के असंगठित श्रमिक जो लंबे समय तक काम करते हैं (जब उन्हें कोई रोजगार मिलता है), काम की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं, खतरनाक और अक्सर अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं, और उनके पास कोई निश्चित नियोक्ता नहीं है या न्यूनतम कमाई का कोई आश्वासन नहीं है, जो देश के 94 प्रतिशत हैं।

मुख्य शब्द : परिचय, अनेक कमियाँ, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

सार

परिचय

भारत के असंगठित श्रमिक जो लंबे समय तक काम करते हैं (जब उन्हें कोई रोजगार मिलता है), काम की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं, खतरनाक और अक्सर अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं, और उनके पास कोई निश्चित नियोक्ता नहीं है या न्यूनतम कमाई का कोई आश्वासन नहीं है, जो देश के 94 प्रतिशत हैं।

वे बच्चों के रूप में काम करना शुरू करते हैं और तब तक काम करते रहते हैं जब तक वे बहुत बूढ़े नहीं हो जाते या जब तक बीमारी या विकलांगता उन पर हावी नहीं हो जाती। वे "अस्वतंत्र" हैं - गरीबी, शोषण, भेदभाव और निरंतर प्रवाह से बंधे हुए हैं। इन "मुक्त" लोगों में भारत में सभी महिला श्रमिकों में से 95 प्रतिशत और सभी पुरुष श्रमिकों में से 89 प्रतिशत शामिल हैं और वे मिलकर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं।

18 दिसंबर 2008 को संसद ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 को मंजूरी दे दी और इस प्रकार यह एक अधिनियम में परिवर्तित हो गया। इन श्रमिकों की स्थिति की जांच करने वाले कई आयोगों के साथ-साथ ग्रामीण मजदूरों और असंगठित श्रमिकों के जमीनी स्तर के संगठनों और यहां तक छिक पार्टियों के राजनेताओं ने भी स्वतंत्र भारत के बाद उनकी स्थिति के बारे में कई चिंताएं उठाई हैं। इसलिए उम्मीदें अधिक थीं कि इस तरह के कृत्य में "अस्वतंत्र" लोगों को स्वतंत्रता दिलाने की शक्ति होगी।

अनेक कमियाँ

असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने के पहले प्रयास के रूप में इस अधिनियम का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन आयोगों से जो एकमात्र सिफारिश स्वीकार की गई है वह श्रमिकों के पंजीकरण और स्मार्ट कार्ड के रूप में पहचान पत्र जारी करने की है। अद्वितीय सामाजिक सुरक्षा नंबर. हालाँकि अपने वर्तमान स्वरूप में यह श्रमिकों को उनके अधिकार सुनिश्चित करने में कम है।

(1) मौजूदा बीपीएल योजनाओं का संकलनः यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बनाने में सक्षम बनाता है। अनुसूची 1 में उन योजनाओं की सूची है जो आज उन श्रमिकों के लिए मौजूद हैं जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में आते हैं।

जना, आम आदमी बीमा योजना, और राष्ट्रीय बीमा योजना)। प्रश्न यह है कि जब ये योजनाएँ पहले ही तैयार की जा चुकी थीं तो एक नए अधिनियम की आवश्यकता क्यों थी? यह अधिनियम वर्तमान या भविष्य की सरकारों के लिए एक भी नई योजना शुरू करना अनिवार्य नहीं बनाता है और उस हद तक यह श्रमिकों को वास्तविक लाभ के माध्यम से कुछ भी नया सुनिश्चित नहीं करता है।

साथ ही, ये मौजूदा योजनाएं बीपीएल श्रेणी के लिए हैं और असंगठित श्रमिकों को बीपीएल और गैर-बीपीएल श्रेणियों में विभाजित करके उनके खिलाफ गंभीर अन्याय किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (2007) ने सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा की कल्पना की थी और इसे अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के प्रत्येक श्रमिक को कुछ बुनियादी अधिकार मिले।

(2) वेतन के मुद्देः आज तक न्यूनतम वेतन राज्य सरकारों द्वारा, राज्य के क्षेत्रों के अनुसार, और श्रमिक के व्यवसाय और कौशल के अनुसार तय किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी को न तो समय पर संशोधित किया जाता है और न ही इसे थोड़ी गंभीरता से लागू किया जाता है। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अधिनियम ने एक गहरी चुप्पी साध रखी है।

वेतन का भुगतान न करना, न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करना, भुगतान में देरी, असमान पारिश्रमिक आदि जैसी कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए कोई दंडात्मक धारा नहीं है। वेतन संबंधी समस्याएं असंगठित क्षेत्र की एक नियमित विशेषता हैं। इस क्षेत्र की संरचना ही ऐसी है कि श्रमिक, विशेषकर प्रवासी और महिला श्रमिक पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। तथ्य यह है कि वे संगठित नहीं हैं और उन्हें संगठित करने में गंभीर संरचनात्मक समस्याएं हैं, यह दर्शाता है कि उन्हें अपने वेतन के संबंध में सरकार की विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। अन्य सभी सामाजिक सुरक्षा उपाय तभी सार्थक होते हैं जब श्रमिक द्वारा अर्जित मजदूरी (हम न्यूनतम मजदूरी या उचित मजदूरी के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनुबंध के हिस्से के रूप में कड़ी मेहनत से अर्जित मजदूरी)

सुनिश्चित की जाती है। मजदूरी का भुगतान न करना एवं टीका नीति निर्माताओं द्वारा स्वीकार की गई तुलना में अत्यधिक देरी कहीं अधिक व्याप्त है। कोई भी योजना श्रमिक को इतनी सुरक्षा नहीं दे सकती जितनी यह ज्ञान कि उसका उचित वेतन समय पर भुगतान किया जाएगा।

यह बुनियादी सुरक्षा थी जिसे अधिनियम को सुनिश्चित करना चाहिए था। जिस श्रमिक को नियोक्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, उससे शक्तिशाली नियोक्ताओं के खिलाफ श्रम न्यायालय में जाने की अपेक्षा करने की वर्तमान प्रणाली, जबकि उसके पास अगला भोजन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, न्याय का मजाक है। वास्तव में, 1988 की श्रमशक्ति रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए त्रिपक्षीय बोर्डों के माध्यम से विवाद समाधान के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, किसी भी सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए श्रमिकों का योगदान मांगने का अधिकार नहीं है, जब वह उचित मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहती है।

(3) शिकायत निवारणः अधिनियम एक अव्यवहारिक प्रावधान के साथ आया है कि सरकार द्वारा बनाई गई प्रत्येक योजना में शिकायत निवारण का अपना तंत्र शामिल होगा। महाराष्ट्र में लेखक के अनुभव से पता चलता है कि निराधार योजना (लाभार्थियों में महिलाओं का बड़ा प्रतिशत, निराश्रित व्यक्तियों के लिए सामाजिक सहायता योजनाएं) की महिला लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, देरी और उत्पीड़न सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैंकों और डाकघरों के रूप में। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई आधिकारिक मंच मौजूद नहीं है कि इस तरह की शिकायतों को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। भविष्य में इनसे तब तक गंभीरता से नहीं निपटा जाएगा जब तक कि यह दृष्टिकोण न अपनाया जाए कि सरकार नागरिक-श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित कर रही है और योजनाएं लाकर वादाखिलाफी नहीं कर रही है। यह उम्मीद की गई थी कि यह अधिनियम श्रमिकों की शिकायत के लिए एक सस्ता, त्वरित और सुलभ मंच लेकर आएगा, लेकिन इस दिशा में केवल आधा-अधूरा और आत्म-पराजित प्रयास ही हुआ है।

(4) काम की स्थितियाँः यह समझना कठिन है कि हमारे सांसदों ने इन श्रमिकों को सामना करने वाली अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों और लंबे समय तक काम करने के बारे में ज़रा भी विचार क्यों नहीं किया। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि आठ घंटे का कार्य दिवस, भले ही कानून बना दिया गया हो, कागज पर ही रहेगा (जो कि देश में अधिकांश सामाजिक न्याय कानून के लिए सच है), ऐसे प्रावधानों ने उन सिद्धांतों के लिए कुछ कहा होगा जिन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। कानून ताकत देता है कार्यकर्ता और उनके संगठन जो जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं।

(5) श्रमिक सुविधा केंद्र और पंचायती राज संस्थाएँः यह अधिनियम दो संरचनाओं की पूरी क्षमता का दोहन करने में विफल रहता है जो एक साथ मिलकर इस अधिनियम को सशक्त बना सकते थे। ये हैंः (ए) श्रमिक सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसी), और (बी) पंचायती राज संस्थान। अपनी गतिविधियों को जागरूकता पैदा करने और

आवेदनों के लिए क्लीयरिंग हाउस के रूप में कार्य करने के बजाय, डब्ल्यूएफसी को श्रमिकों के पंजीकरण और स्थानीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाए रखने का काम सौंपा जा सकता था। डब्ल्यूएफसी को ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए और श्रमिकों तक लाभ पहुंचाने के लिए इसे ग्राम पंचायतों या नगर निकायों से जोड़ा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त श्रमिक ठेकेदारों का रिकॉर्ड बनाए रखने का काम दिया जाना चाहिए था क्योंकि इससे मानव तस्करी और बिना लाइसेंस वाले ठेकेदारों द्वारा श्रम के शोषण को रोकने में काफी मदद मिलती। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत को उन ठेकेदारों का रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए जो गांव में मजदूरों की खरीद के लिए आते हैं और उन मजदूरों का विवरण रखते हैं जिन्हें क्षेत्र के बाहर काम के लिए ले जाया जाता है।

- या तो एक ही जिले या राज्य में या अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के रूप में। ऐसी स्थिति में जहां एक प्रवासी मजदूर या महिला मजदूर को परेशान किया जाता है, यातना दी जाती है या मजदूरी नहीं दी जाती है और सामान्य परिस्थितियों में कहीं नहीं जाना है, डब्ल्यूएफसी उनकी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था।

(6) महिला श्रमिकः अधिनियम में महिला श्रमिकों के संबंध में विशेष रूप से समान पारिश्रमिक, सभ्य कार्य स्थितियों और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। वर्तमान योजनाएं महिलाओं की जरूरतों को मां या विधवा के रूप में उनकी भूमिकाओं के संदर्भ में देखती हैं और हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि श्रमिकों के रूप में उनकी जरूरतों को भी संबोधित किया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों के मुद्दों पर केंद्रित श्रमशक्ति रिपोर्ट (1988) की सिफारिशें अधिनियम में प्रतिबिंबित होनी चाहिए थीं। इसी तरह, विशाखा बनाम राज्य (1997) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित किया गया था, को इस अधिनियम में जगह मिलनी चाहिए थी।

दान, अधिकार नहीं कुल मिलाकर, अधिनियम की भाषा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रमिकों के बराबर अधिकार देने वाली नहीं है व संगठित क्षेत्र, बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में उनकी स्थिति को सीमित करना। अधिनियम के भीतर कुछ स्थान बचे हैं जिनके माध्यम से इनमें से कुछ चिंताओं को संबोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड हैं, जिन्हें केंद्र (या राज्य, जैसा भी मामला हो) को उपयुक्त योजनाओं की सिफारिश करने की शक्ति दी गई है।"असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विभिन्न वर्ग" और "केंद्र (या राज्य) सरकार द्वारा संचालित असंगठित कार्यों के लिए ऐसी सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी भी करें"। आशा है कि इन बोर्डों का गठन बुद्धिमानी से किया जाएगा और उन्हें असंगठित श्रमिकों के मुद्दों को अधिक विशिष्ट विवरण में देखने का अधिकार दिया जाएगा। हालाँकि, श्रमिकों के अधिकारों के रूप में जिसे अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए था, उसे अब अधिक से अधिक क्रमिक रूप से शामिल किया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

भारत में असंगठित क्षेत्र विशाल स्तर पर है। साथियों हम आगे चर्चा करें इसके पहले हमें संगठित और असंगठित श्रमिकों के बारे में समझना होगा। संगठित क्षेत्र वह है जो उचित प्राधिकारी या सरकार के साथ शामिल हो और उसके नियमों और विनियमों का पालन करे। इसके विपरीत, असंगठित क्षेत्र को सेक्टर के रूप में समझा जा सकता है, जो सरकार के साथ शामिल नहीं है और इस प्रकार, किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों असंगठित क्षेत्र वह सेक्टर हैं जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है और जिसके रोजगार की शर्तें तय नहीं हैं और नियमित रूप से असंगठित क्षेत्र माना जाता है। इस सेक्टर मेंकिसी भी सरकारी नियम-कानून का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे क्षेत्र में प्रवेश काफी आसान है क्योंकि इसकेलिए किसी संबद्धता या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सरकार असंगठित क्षेत्रको विनियमित नहीं करती है, और इसलिए कर नहीं लगाया जाता है। इस क्षेत्र में उन छोटे आकार के उद्यम, कार्यशालाएं शामिल हैं जहां कम कौशल औरअनुत्पादक रोजगार हैं। साथियों बात अगर हम असंगठित क्षेत्र की करें तो, असंगठित क्षेत्र की खास बात यह है कि वहां ज्यादातर श्रम कानून लागू नहीं होते है। इसमें काम करने वालों की दशा दयनीय है। न वे सुनिश्चित रोजगार पाते हैं, न उनको सही वेतन मिलता है और न ही उन्हें कोई कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।

इस क्षेत्र में रोजगार हमेशा नहीं होता एवं इसलिए काम की कोई गारंटी नहीं, दिनांक 17 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में 3 मजदूरों को गोली मारी जिसमें दो की मृत्यु हो चुकी है, 16 अक्टूबर 2021 को भी जम्मू कश्मीर में रेहड़ी पटरी वाले हॉकर को गोली मारी गई थी जिस की घटनास्थल पर मृत्यु हुई थी। साथियों बात अगर हम आंकड़ों की करें तो विशेषज्ञों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में 50 फ़ीसदी से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्यबल में हिस्सा 80 फ़ीसदी है। साथियों अधिकतम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले खुदरा बाजार, कृषि, निर्माण कार्य, थोक कारोबार क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करने वाले हैं, परंतु वर्तमान समय में अधिकतम रोजगार सृजन की संभावना कृषि और निर्माण कार्य क्षेत्र में अधिक नजर आ रही है भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से बना है और इसमें वे लोग शामिल हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं।

भारत के श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रम बल को चार भागों में बांटा है व्यवसाय, रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी और सेवा श्रेणी। साथियों शुरू से ही असंगठित क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं अस्थाई रोज़गार श्रम कानूनों के तहत नहीं आते, सामाजिक सुरक्षा की कमी, बढ़ती जटिल आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था, खतरनाक उद्यमों में भी सुरक्षा नहीं, बेहद कम आमदनी, रोजगार और रोजी की अस्थिरता, आर्थिक सहायता मुआवजे का नियम नहीं, इत्यादि काफी जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं। असंगठित क्षेत्र की रही सही कसर पिछले साल 2020 से अभी तक भयंकर त्रासदी दे रही कोरोना महामारी ने निकाल ली है क्योंकि कोरोना महामारी के

दुष्प्रभाव से लॉकडाउन, आर्थिक मोर्चाबंदी, बेरोजगारी ने असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ कर रख दी है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए अनेक आर्थिक पैकेज व सहायता तथा दिवाली 2021 तक 80 फ़ीसदी लोगों को 5 किलो अनाज श्री उपलब्धि की योजनाएं दी है, फ़िर भी असंगठित क्षेत्र की समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है इसलिए इसका संज्ञान केंद्र सरकार ने लिया है और इस श्रमिक पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के रजिस्टर रजिस्ट्रेशन की योजना लागू की है।३साथियों बात अगर हम ई पोर्टल की करें तो दिनांक 17 अक्टूबर 2021 की पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद असंगठित श्रमिकों को एक डिजिटल ई-श्रम कार्ड प्राप्त होगा और वे पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने प्रोफाइल/विवरण को अपडेट कर सकते हैं। उनके पास एक सार्वभौमिक खाता संख्या (ई-श्रम कार्ड पर) होगी जो पूरे देश में स्वीकार्य होगी और अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी ई-श्रम पोर्टलपरपंजीकृत है और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है,तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये प्राप्त करने का पात्र होगा।

साथियों बात अगर हम ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की योग्यता की करें तो,निर्माण, परिधान निर्माण, मछली पकड़ने, गिग और प्लेटफॉर्म वर्क स्ट्रीट वेंडिंग, घरेलू कार्य, कृषि और संबद्ध कार्यों, परिवहन क्षेत्र जैसे विविध व्यवसायों से जुड़े श्रमिकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से कुछ क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या भी जुड़ी हुई है। प्रवासी श्रमिकों सहित सभी असंगठित श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं का लाभले सकते हैं।३साथियों बात अगर हम 17 अक्टूबर 2021 तक की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों की करें तो,नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर 4.09 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है।

इनमें से लगभग 50.02 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं और 49.98 प्रतिशत पुरुष हैं। यह उत्साहजनक है कि पुरुषों और महिलाओंका समान अनुपात इसअभियान का हिस्सा रहा है। लिंग के आधार पर पंजीकरण में साप्ताहिक सुधार होता रहा है, पुरुष और महिला श्रमिकों ने तुलनात्मक अनुपात में पंजीकरण किया है।३साथियों बात अगर हम असंगठित क्षेत्रों की करे तो,भारत में पंजीकृत श्रमिकों की सबसे बड़ी संख्या रोजगार का सृजन करने वाले क्षेत्रों कृषि और निर्माण से है। इसके अतिरिक्ष्त, घरेलू और गृह कार्य से जुड़े श्रमिकों, परिधान क्षेत्र के श्रमिकों, ऑटोमोबाइल और परिवहन क्षेत्र के श्रमिकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर श्रमिकों, पूंजीगत वस्त्तु श्रमिकों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल खुदरा, पर्यटन और आतिथ्य, खाद्य उद्योग तथा अन्य कई जैसे विविध और विभिन्न व्यवसायों के श्रमिकों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।३साथियों बात अगर हम ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की विधि की करें तो, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, व्यक्तिगत श्रमिक ई-श्रम के मोबाइल एप्लिकेशन या वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। वे इस पोर्टल में अपना पंजीकरण कराने के लिए सामान्य

सेवा केंद्रों (सीएससी), राज्य सेवा केंद्र, श्रम सुविधा केंद्रों, डाक विभाग के डिजिटल सेवा केंद्रों के चुने हुए डाकघरों में भी जा सकते हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, रोज़गार और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने ई श्रमिक पोर्टल पंजीकरण मील का पत्थर साबित होगा। ई पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्युपर दो लाख़ स्थाई विकलांगता पर एक लाख़ आर्थिक सहायता का प्रावधान सराहनीय कदम है।

संदर्भ सूची

https://labour.gov.in/sites/default/files/SS%20Policy%20&amp%3B%20Code%20-%20Full%20presentation%2024-4-17.pdf[bare URL PDF]

1. Ashok, Sowmiya (4 April 2020). "Welfare schemes, well-oiled PDS helping Tamil Nadu's poor". Hindustan Times. Retrieved 2 September 2020.
2. Ravi, Reethu (4 May 2020). "COVID-19: West Bengal Announces Rs 10 Lakh Health Insurance For Frontline Workers, Journalists". The Logical Indian. Retrieved 2 September 2020.
3. The Code on Social Security 2020. Ministry of Law and Justice. The Gazette of India.
4. Chakrabarty, Amitava (26 February 2020). "National Pension System: NPS, APY gaining popularity among pension seekers". Financial Express. The Indian Express.
5. Sabharwal, Manish; Mehrishi, Rajiv (21 April 2021). "Covid is an opportunity to make structural changes to our largest health insurance and pension schemes". The Indian Express. Retrieved 30 May 2021.
6. Economic Survey, Government of India. 2022-2023
7. "Expenditure on Social Services increased by more than one percentage points as proportion of GDP during last five years: Economic Survey". Press Information Bureau. Ministry of Finance, Government of India. 4 July 2019.
8. https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/aboutus/committee/wrkgrp/wg_soclsc ty.pdf[bare URL PDF]
9. Dezan Shira & Associates (2013) [2021]. Introduction to the Social Security System in India. Indian Briefing.
10. General Overview. Ministry of Labour and Environment, Government of India.
11. Pellissery, Sony; Jain, Saloni; Varghese, Geo (2020). "Access to Social Protection by Immigrants, Emigrants and Resident Nationals in India". Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 3). IMISCOE Research Series. pp. 147–161. doi:10.1007/978-3-030-51237-8_8. ISBN 978-3-030-51236-1. S2CID 229255287.